देने के लिए अभी तक कुछ प्रोत्साहन योजनाओं को कार्यान्वित किया हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) जी हां।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अति लघु कुटीर क्षेत्र सहित, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन तथा विकास हेतु अवस्थापनापरक सुविधाओं का सृजन करने और प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनागत स्कीमें चला रहा है। इसके अतिरिक्त, लघु क्षेत्र उद्योग को प्रदान की गई सभी सुविधाएं तथा प्रोत्साहन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी उपलब्ध हैं।

लघु उद्योगों के लिए निगरानी व्यवस्था

2367. **श्री राज मोहिन्दर सिंह** :

श्री कपिल सिब्बल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि देश के उन जिलों में जहां एक हजार से दो हजार लघु उद्योग हैं वहां विशेष निगरानी व्यवस्था कायम की जाएगी जो लघु उद्योगों की ऋण संबंधी समस्या पर ध्यान रखेगी:

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की निगरानी व्यवस्था किन-किन राज्यों के कितने-कितने जिलों में स्थापित की गई हैं और

यह निगरानी व्यवस्था किन-किन स्थानो पर स्थापित की गई हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) बैंकों द्वारा लघु उद्योग एककों को वित्त पोषित करने की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरों पर पहले ही निगरानी प्रणालियां मौजूद है। राज्य स्तर पर "राज्य बैंकर समिति" द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण के प्रवाह की निगरानी की जाती है। और यह समिति लघु उद्योगों की ऋण से संबंधित समस्याओं को देखती हैं। जिला स्तर पर लघु एककों में ऋण के प्रवाह की निगरानी बैंकों की जिला समन्वय समिति द्वारा की जाती हैं।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा आधार वर्ष 1987-88 के आधार पर की गयी द्वितीय अखिल भारतीय पंजीकृत लघु उद्योग गणना के अनुसार, लघु उद्योंग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय देश के 119 जिलों में से प्रत्येक में 1000-2000 पंजीकृत लघु उद्योग बैंक शाखाएं चालू की गयी है। मार्च, 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजानिक बैंकों की सलाह दी हैं कि वे और अधिक विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग बैंक शाखाएं खोलने हेतु, केन्द्रों की पहचान करते समय, इन 80 जिलों में केन्द्रों का चुनाव करें।

उन राज्यों की सूची, जिलों की संख्या और उन के नाम सहित, अनुबंध के रूप में संलग्न की गयी हैं जहां 1000-2000 (द्वितीय आखिल भारतीय गणना के अनुसार) के बीच पंजीकृत लघु उद्योग हैं तथा जहां विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग शाखाएं खोली गयी हैं।

1000-2000 (द्वितीय अखिल भारतीय गणन के अनुसार) पंजीकृत लघु उद्योग वाले राज्य/जिले जहां विशेषज्ञता प्राप्त लघु बैंक शाखाएं खोली गयी हैं।

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिलो की संख्या	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	विशाखापत्तम, वारंगल
2.	बिहार	1	सिंहभूम
3.	गुजरात	5	भावनगर, जामनगर, मेहंसाना, मारूच, जूनागढ़
4.	हरियाणा	1	सोनीपत
5.	कर्नाटक	3	तुपकुरू, कोलार, हसन
6.	केरल	2	कन्नौर, मालापुरम

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया अनुदान

2370. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को जिला-वार कितना अनुदान आबंटित किया गया हैं;

(ख) इन अनुदानों से कितने युवा लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए निधि संग्रह में वृद्धि करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्यों के लिए भौतिक लक्ष्य आवंटित करती हैं ताकि अति लघु उद्यम स्थापित करने में बेरोजगार शिक्षित युवकों की सहायता की जा सकें। राज्य सरकारें फिर अपने जिलों में जिला-वार लक्ष्य आबंटित करती है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को उनके संबंधित राज्यों में योजना की प्रगति के अनुसार प्रशिक्षण और संचालनात्मक प्रयोजनों, इत्यादि के लिए निधियां प्रदान करती हैं। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1996-97, 1997-98 और 14998-99 (11 दिसम्बर, 1998 तक में जारी की गई निधियां क्रमशः 260.40

लाख रू. 368.95 लाख रूपये 270.51 लाख रूपये (11 दिसम्बर, 1998 तक हैं) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (अक्तूबर 1998 तक) के जिलावार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां (बैंकों द्वारा स्वीकृतियों और संवितरण) क्रमशः विवरण I, विवरण II और विवरण III में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, 1 लाख रूपये की लागत वाली अलग-अलग परियोजनाओं के वित्तीय पैटर्न इस प्रकार हैं:-

विवरण

वर्ष 1996-97 हेतु उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना की प्रगति

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार

क्रम संख्या	जिले का नाम	1996-97 लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृत (संख्या)	बैक द्वारा वितरित (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आगर	677	730	576
2.	अलीगढ़	779	890	737
3.	एटा	575	652	568
4.	मथुरा	495	602	524
5.	मेनपुरी	350	368	278
6.	फिरोजाबाद	393	406	323
7.	इलाहाबाद	1211	1212	941
8.	फतेहपुर	505	508	382
9.	प्रतापगढ़	544	563	353
10.	आजमगढ़	589	589	527